प्रेस विज्ञप्ति

29 नवंबर, 2016

<u>श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी व कु. सुश्मिता देव, सांसद एवं प्रवक्ता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया</u> :–

नोटबंदी की ऐतिहासिक भूल और देशव्यापी विफलता पर माफी मांगने की बजाए प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी नित नए जुमले, झूठे बहाने और गुमराह करने वाले अफसाने ढूंढने में लगे हैं। देश का ध्यान बांटने के लिए मोदी जी आए दिन नई नाटकीयता, झूठी भावुकता या अजीबोगरीब शगूफे लेकर आते हैं।

कालाधन से लड़ने का दंभ भरने वाले मोदी जी न तो भाजपा के खातों और संपत्ति का हिसाब देते और न ही नोटबंदी के घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से करवाते। देश की आंखों में धूल झोंकने के लिए आज मोदी जी ने एक नया जुमला दे डाला। भाजपा सांसदों व विधायकों को 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक अपने खातों का विवरण भाजपा अध्यक्ष, श्री अमित शाह को देने के लिए कहा। यह जुमला इसलिए छोड़ा गया कि देश भर से मांग उठी कि भाजपा, आरएसएस व भाजपा नेता 8 नवंबर की नोटबंदी से पहले खातों का विवरण व भाजपा द्वारा संपत्ति खरीद का विवरण सार्वजनिक करें। यदि भाजपा व आरएसएस 8 नवंबर की नोटबंदी से 12 महीने पहले तक अपने सभी खाते तथा संपत्ति खरीद का ब्यौरा सार्वजनिक कर दें, तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। देशवासियों की ओर से हम मोदी जी को चुनौती देते हैं कि पारदर्शिता की कसौटी पर खरे उतरने का यही एकमात्र मापदंड है।

नोटबंदी के घोटाले के रहस्य की परतें आए दिन खुल रही हैं। संपूर्ण देश ने नोटबंदी यानि 8 नवंबर के दिन भाजपा की कलकत्ता इकाई के बैंक खाते में यकायक 500 और 1000 रु. के नोटों में लगभग 1 से 3 करोड़ की राशि का विवरण देखा। इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर बिहार में नोटबंदी से ठीक पहले यानि अगस्त और सितंबर माह में खरीदी हुई जमीन–जायदाद का खुलासा भी सार्वजनिक हुआ।

इसी कड़ी में और सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा प्रांत के 18 जिलों में बिहार की तर्ज पर संपत्ति खरीदी है। उदाहरण के तौर पर 30 अगस्त, 2016 को गोप ट्रैफिक जंक्शन, नज़दीक आरटीओ ऑफिस, राष्ट्रीय राजमार्ग 5, केंद्रापाड़ा में 2 एकड़ भूमि भाजपा द्वारा 45 लाख रु. में खरीदी गई। इस ज़मीन की वास्तविक कीमत इससे भी कई गुना ज्यादा है। इसी प्रकार 19 सितंबर, 2016 को 1125 गज जमीन जगतसिंहपुर अर्बन एरिया में भाजपा द्वारा खरीदी गई, जिसकी वास्तविक लागत कहीं अधिक है। इसी कड़ी में अक्टूबर, 2016 में 10,000 वर्गफीट जमीन, राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीक, बुरहामपुर, उड़ीसा में 20 लाख रु. की लागत से भाजपा द्वारा खरीदी गई। इसी प्रकार बड़मल, झारसुगड़ा में 1 प्लॉट बीजूमल पटनायक चख़ के साथ खरीदा गया।

कालेधन के रहस्य की परतें व नोटबंदी का घोटाला आए दिन खुलता जा रहा है। भाजपा ने नोटबंदी से कुछ महीने पहले भारी राशि का निवेश पूरे देश में अलग–अलग संपत्तियां खरीदने के लिए किया। देशवासी जवाब मांग रहे हैं कि पारदर्शिता व जवाबदेही की दुहाई देने वाले श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा तथा आरएसएस के नोटबंदी से 12 महीने पहले तक के सभी संपत्ति खरीद का विवरण तथा सभी खातों का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि कालेधन की, अरबों रुपये के निवेश की व पैसे के स्रोत की असलियत सामने आ जाए।

सच यह है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी नए–नए तरीकों से कालाधनधारकों को संरक्षण दे रहे हैं। सबसे पहले तो मोदी जी ने कालाधन सफेद बनाने के लिए एक fair and lovely स्कीम चलाई, जो 1 जून, 2016 से 30 सितंबर, 2016 तक थी और जिसमें घोषित काला धन के ऊपर 45% टैक्स देकर उसे सफेद बनाया जा सकता था। इसके ठीक बाद मोदी जी अपना 8 नवंबर, 2016 का नोटबंदी का तुगलकी फरमान ले आए। अब जब नोटबंदी का फरमान औंधे मुंह पड़ा, तो काला धन से लड़ाई लड़ने की बजाए, मोदी जी इंकम टैक्स कानून में संशोधन कर 'कालाधनधारक कल्याण योजना' लेकर आए हैं, जिसे 'गरीब' के नाम का झूठा अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। एकबार फिर 49.5% टैक्स जमा करवाकर काला धन को सफेद बनाने की खुली छूट कालाधनधारकों को दे डाली है। इंकम टैक्स कानून के धारा 271 (1) (C) (iii) के मुताबिक कालाधन पकड़े जाने पर 132% टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। परंतु कालाधनधारकों की मदद के लिए मोदी सरकार एके के बाद एक कर दो स्कीम ले आई है, ताकि न जुर्माना लगे, न सजा हो और कालाधन भी आसानी से सफेद बन जाए। इस पर भी ये मनमानी कि संसद में पोल खुलने के डर से इंकम टैक्स कानून के इस संशोधन को मनी बिल की संज्ञा तक दे डाली गई। न चर्चा और न ही संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता। सीनाजोरी, मनमानी और संसद का अपमान अब कालाधनधारकों की मदद की नई कसौटी बन गया है।

मोदी सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। समय आ गया है कि मोदी जी जुमलों का मुखौटा उतारें और राजधर्म की पालना करें।